

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1148
28.06.2019 को उत्तर के लिए

समुद्रतटों हेतु ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र

1148. श्री जी०एम० सिद्देश्वरा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारतीय समुद्रतटों को ब्लू फ्लैग मानकों के अनुसार विकसित करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस परियोजना के अन्तर्गत ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए तटीय राज्यों का चुनाव किया गया है; और
- (घ) यदि हां, तो चयन किए गए समुद्रतटों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ब्लू फ्लैग मानकों के अनुसार समुद्रतटों को विकसित करने के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना चरण-1, के तहत समुद्र तट पर्यावरण एवं सौंदर्य प्रबंधन प्रणाली (बीम्स) (बीईएएमएस) कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के तहत, समुद्र तट के लिए ब्लू फ्लैग मानक प्राप्त करने के लिए अभिज्ञात समुद्र तटों में प्रदूषण उपशमन समुद्रतट का सौंदर्यीकरण के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमलाप, पर्यावरण शिक्षा और सुरक्षा व निगरानी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(ग) और (घ) बीईएएमएस कार्यक्रम के तहत दियु में गोघला समुद्र तट, गुजरात में शिवराजपुर समुद्र तट, कर्नाटक में पाडूबिदरी और कसारकोड समुद्र तट, केरल में कप्पाड समुद्र तट, तमिलनाडु में महाबलीपुरम समुद्र तट, पुडुचेरी में ईडन समुद्र तट, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा समुद्र तट, ओडिशा में गोल्डन समुद्रतट और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में राधानगर समुद्र तट का ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चयन किया गया है।
